

वशिष ववाह अधनियम 1954

प्रलिमिंस के लयि:

वशिष ववाह अधनियम (SMA), 1954, मौलकि अधकिार

मेन्स के लयि:

वशिष ववाह अधनियम (SMA), 1954, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम यूओआई (2017), नजिता का अधकिार, व्यक्त्गित स्वतंत्रता ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में देश में अंतर-धार्मकि ववाहों को नयितरति करने वाले कानून, वशिष ववाह अधनियम (SMA), 1954 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई ।

- वर्ष 2021 में इसके कई प्रावधानों को रद्द करने के लयि याचकिारुँ दायर की गई ।

वशिष ववाह अधनियम (SMA), 1954:

- वशिष ववाह अधनियम भारत में अंतर-धार्मकि एवं अंतरजातीय ववाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है ।
- यह एक नागरकि अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्त्तियों को अपनी शादी वधिपूरवक करने की अनुमति देता है ।
- अधनियम के तहत कसिी धार्मकि औपचारकिता के नरिवहन की आवश्यकता नहीं होती ।
- इस अधनियम में हद्दू, मुसलमि, ईसाई, सखि, जैन और बौद्ध ववाह शामिल हैं ।
- यह अधनियम न केवल वभिन्नि जातयिों और धर्मों के भारतीय नागरकिों पर बल्क विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरकिों पर भी लागू होता है ।

वर्तमान याचकिा के बारे में:

- SMA की धारा 5 में इस कानून के तहत शादी करने वाले व्यक्त्तको इच्छति ववाह की सूचना देने की आवश्यकता होती है ।
- धारा 6(2) के मुताबकि, इसे ववाह अधकिारी के कार्यालय में एक वशिषिट स्थान पर चपिका दया जाना चाहयि ।
- धारा 7(1) कसिी भी व्यक्त्तको नोटसि के प्रकाशन के 30 दनिों के भीतर ववाह पर आपत्ता करने की अनुमति देती है, ऐसा न करने पर धारा 7(2) के तहत ववाह संपन्न कया जा सकता है ।
- व्यक्त्गित स्वतंत्रता को प्रभावति करने वाले इन प्रावधानों के कारण कई अंतर-धार्मकि जोड़ों ने अधनियम की धारा 6 और 7 को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी ।

प्रमुख बदि

- अंतर-धार्मकि ववाह**
 - अंतर-धार्मकि ववाह का आशय अलग-अलग धार्मकि आस्थाओं वाले दो व्यक्त्तियों के बीच वैवाहकि संबंध से है ।
 - एक अलग धर्म में शादी करना कसिी वयस्क के लयि अपनों व्यक्त्गित पसंद का मामला है ।
- अंतर-धार्मकि ववाह से संबंधति मुद्दे:**
 - माना जाता है क् अंतर-धार्मकि ववाह के तहत पति-पत्नी (ज्यादातर महलारुँ) में से कसिी एक का जबरन धर्मांतरण होता है ।
 - मुसलमि परसनल लों के अनुसार, गैर-मुसलमि से शादी करने के लयि धर्म परिवर्तन ही एकमात्र तरीका है ।
 - हद्दू धर्म केवल एक ववाह की अनुमति देता है और जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं वे दूसरा रास्ता अपनाते हैं ।
 - ऐसे ववाहों से पैदा हुए बच्चों के जाति निरिधारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है ।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 समाज के पछिड़ेपन के अनुकूल नहीं है।
- उच्च न्यायालय द्वारा अंतर-धार्मिक विवाह को रद्द करने के संदर्भ में अनुच्छेद 226 की वैधता पर बहस चल रही है।
 - अनुच्छेद 226: रटि जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति।
- अंतर-धार्मिक विवाहों से संबंधित कानूनों पर विचार करते समक्ष चुनौतियाँ:
 - मौलिक अधिकारों के विरुद्ध: किसी व्यक्ति को विवाह के चुनाव में कानून का हस्तक्षेप उसके मौजूदा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जैसे:
 - समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)।
 - स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
 - धर्म की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 21)।
 - धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध: भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख सिद्धांतों में शामिल किया गया है।
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
 - इसलिये भारत में अंतर-धार्मिक विवाहों की अनुमति है क्योंकि संविधान किसी भी व्यक्ति को अन्य धर्म को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न नरिणयों के साथ भिन्नता:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोक केएम (2018) मामले में अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-शैली या विश्वास का पालन करने की क्षमता को सुरक्षित करता है जिसका वह पालन करना चाहता है।
 - इसलिये अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
 - इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में [के.एस. पुट्टस्वामी बनाम यूओआई \(2017\)](#) के फैसले ने "पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में माना है।
 - पतृसत्तात्मक: इससे पता चलता है कि कानून की जड़ें पतृसत्तात्मक हैं, जिसमें महिलाओं को माता-पिता एवं सामुदायिक नियंत्रण में रखा जाता है और यहाँ तक की जीवन के नरिणय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है, अगर वे नरिणय उनके अभिभावकों को स्वीकार्य न हो।

आगे की राह

- किसी भी कानून को शामिल करने से बचने के लिये मानसिक और सामाजिक स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की स्वीकृति होनी चाहिये।
- अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिये, केवल विवाह हेतु धर्म परिवर्तन करना बलिकूल भी बुद्धिमानी नहीं है।

स्रोत: द हट्टू